बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 124

व्यापक सुधार जरूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सरकारी बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करके बाजार को चौंका दिया। बाजार को इस मद में 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन की आशा थी। किस बैंक को कितनी राशि मिलती है, इस आधार पर अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल इन बैंकों द्वारा वृद्धि पूंजी के रूप में किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र का फंसा हुआ कर्ज कम हुआ है और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के कारण सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के ऋण प्रवाह की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार फंसे हुए कर्ज का काफी हिस्सा चिह्नित किया जा चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह चक्र बदल चुका है। यह अच्छी खबर है, हालांकि सरकारी बैंकों को अभी भी फंसे हुए कर्ज की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेने में समय लग सकता है क्योंकि वह 12 फीसदी से ऊपर है।

बहरहाल, बड़ा सवाल यह है कि क्या नए सिरे से पूंजी डालने के बाद सरकारी बैंकों में हालात बदलेंगे? सरकारी बैंकों के नजरिये से देखा जाए तो फंसे हुए कर्ज को चिह्नित करने, उसका निस्तारण करने और पुनर्पूंजीकरण करने, सभी स्थितियों में सुधार हुआ है लेकिन चौथा घटक यानी सुधार अभी भी नदारद है। अगर व्यापक सुधारों की शुरुआत नहीं की गई तो पुनर्पूंजीकरण के लिए धन की जरूरत पड़ती रहेगी। यह भी तय है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता की समस्या केवल झूठे आशावाद और कारोबारी जगत की अतिशय उधारी की देन नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बैंक, खासतौर पर सरकारी बैंक जोखिम का सही आकलन करने में चूक गए।

इस संदर्भ में देखा जाए तो सरकारी बैंकों की परिचालन किफायत सुधारने के लिए सरकार को कई स्तरों पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों को केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण से मुक्त करना होगा। उनका नियमन निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह करना होगा। इसके अलावा यह भी अहम है कि सरकारी बैंकों के बोर्ड पेशेवर हों और उनको परिचालन में पूरी स्वतंत्रता हासिल हो। इससे उनको अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। सरकारी बैंकों को मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भी सुधार करने की आवश्यकता है। यह बात अहम है कि वेतन भत्ते बाजार और प्रदर्शन दोनों से संबद्ध हों। इससे सरकारी बैंकों को सही लोगों को चुनने में मदद मिलेगी। कारोबार और वित्त जगत की बढ़ती जटिलता के दौर में बैंकों को विशिष्ट कौशल वाले लोगों की आवश्यकता है, तभी वे जोखिम का प्रबंधन कर सकेंगे। सरकारी बैंकों के बैंकरों को जांच एजेंसियों से बचाना भी अहम है। खासकर उन मामलों में जहां वाणिज्यिक निर्णय गलत साबित होते हैं। अनावश्यक रूप से लंबी जांच प्रक्रिया में उलझने के डर से निर्णय प्रक्रिया में धीमापन आता है और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह कमजोर पड़ता है।

स्पष्ट है कि सरकार के लिए इन सुधारों को लागू करना आसान नहीं होगा। सार्थक बदलाव तभी हो सकता है जब बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम हो। देश के राजकोषीय हालात की बात करें तो सरकार को सरकारी बैंकों के बारे में निर्णय लेना होगा। बजट की सीमा सरकार को इन बैंकों के ज्यादा पुनर्पूंजीकरण की इजाजत नहीं देगी और पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड का नियमित इस्तेमाल देश के राजकोषीय प्रबंधन में भरोसा खत्म करने का काम करेगा। चूंकि सरकार अब विदेशों से ऋण लेने की योजना बना रही है इसलिए बढ़ी हुई जवाबदेही और कमजोर सरकारी बैंक भारतीय बॉन्ड और रेटिंग पर दबाव बना सकते हैं। घरेलू स्तर पर, कमजोर सरकारी बैंक पूंजी के किफायती आवंटन को रोकेंगे और देश के सकल घरेलू उत्पाद को 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को बाधित करेंगे।

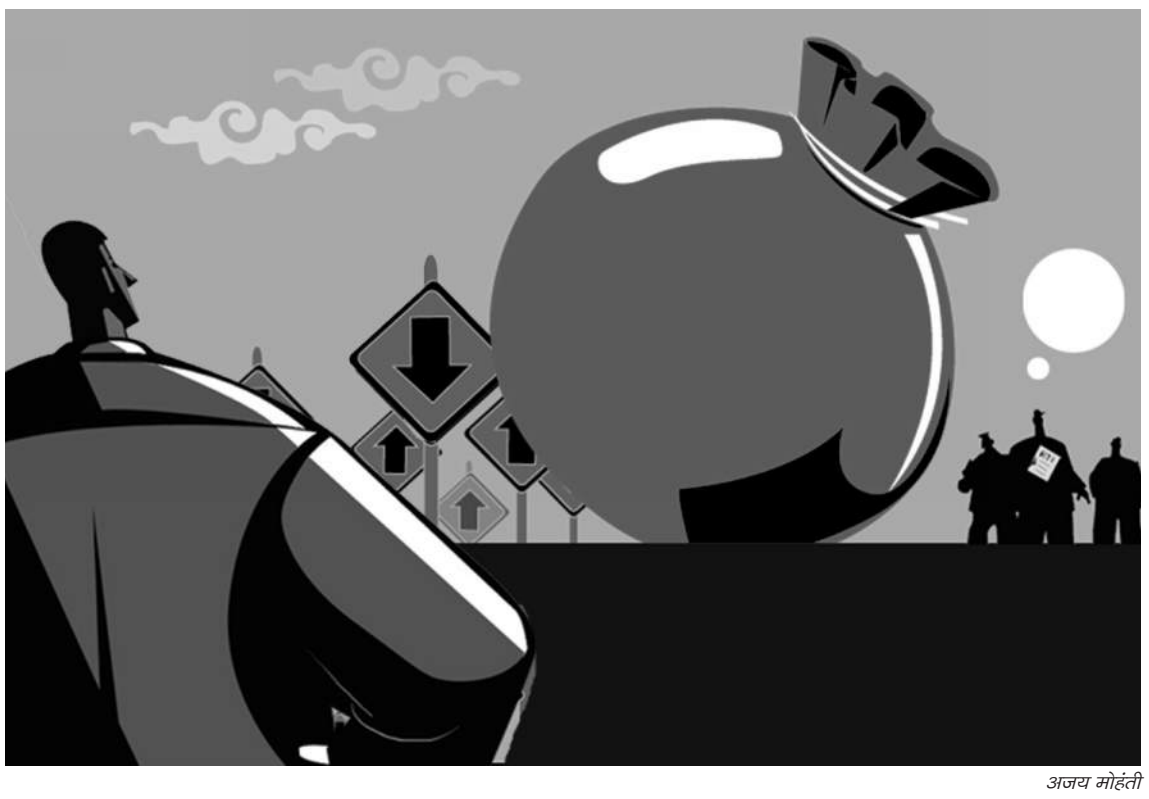

अजय मोहंती

वित्तीय क्षेत्र सुधार के अनचाहे परिणाम

फिलहाल डेट बाजार में जो संकट नजर आ रहा है, उसकी वजह है वित्तीय क्षेत्र की बेहतरी के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **आकाश प्रकाश**

भारतीय वित्तीय व्यवस्था एक अप्रत्याशित सफाई के दौर से गुजर रही है। अंकेक्षकों और रेटिंग एजेंसियों से लेकर बैंकों और फंड तक हर जगह मानक कड़े किए जा रहे हैं। लंबी अवधि में इसके अनेक लाभ सामने आएंगे। व्यवस्था का प्रबंधन करके चीजों को ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। रसूख के बल पर ऋण का सिलसिला भी लंबा नहीं चल सकता। तमाम बाजार प्रतिभागी आशंकित हैं और अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। काम करने या न करने वालों की जवाबदेही भी तय हो रही है।

इस प्रक्रिया की शुरुआत ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के क्रियान्वयन के साथ हुई थी जहां पहले बड़े निस्तारण के बाद प्रवर्तकों को अहसास हुआ था कि पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे और वे कंपनियों पर से नियंत्रण गंवा सकते हैं। कर्ज का अपना असर होता है। कंपनी स्तर पर ज्यादा कर्ज आपसे कंपनी का नियंत्रण छीन सकता है। प्रवर्तक स्तर पर ज्यादा कर्ज परिसंपत्ति पर से नियंत्रण छीन सकता है। कर्ज हमेशा से दोधारी तलवार रहा है। हमारे यहां अतीत में ज्यादा कर्ज के अधिक जोखिम नहीं थे लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

ज्यादा कर्ज और उसे चुका पाने में नाकामी के अब कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि देश भर में कंपनियां और प्रवर्तक समूहों की बैलेंस शीट में कर्ज कम किया जा रहा है। कर्ज के स्वीकार्य स्तर की परिभाषा बदल चुकी है। बैलेंस शीट में मंदी आईबीसी का अनचाहा परिणाम है। इससे तंत्र में डेट और इक्विटी का अनुपात कम होगा। यही कारण है कि सरकार को निवेश पर जोर जारी रखना होगा। बैलेंस शीट की इस मंदी के बीच निजी क्षेत्र निवेश नहीं करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरें कितनी कम हैं। अगर आप नकदीकरण के इच्छुक हैं तो अपना जोखिम कम करने के लिए आप नया कर्ज नहीं लेंगे।

नकदी की आवक का इस्तेमाल नई परियोजनाओं में नहीं किया जाएगा बल्कि उसका इस्तेमाल डेट-इक्विटी का मिश्रण सुधारने के लिए किया जाएगा। दरों में 100 या 200 आधार अंक की कमी से निवेशकों का मन नहीं बदलेगा। समूचे कारोबारी जगत में अगर आप 50 प्रमुख कारोबारी घरानों पर नजर डालें तो हर कोई नकदी कम कर रहा है।

यह सफाई आवश्यक है। हालांकि नकदी की कमी वृद्धि पर असर डाल रही है। परंतु आने वाले दिनों में यह वित्तीय तंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। समस्त बाजार प्रतिभागियों में मानक और परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार होगा। खुलासे, रेटिंग, अंकेक्षण नोट आदि बाजार को मजबूती देंगे। हम बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। मजबूत और अच्छी तरह संचालित कंपनियां वित्तीय जगत को बेहतर बनाएंगी। निकट भविष्य में सरकार को तयशुदा परिसंपत्ति निवेश पर ध्यान देना होगा। बजट से पता चलेगा कि इन निवेश के लिए संसाधन कहां से आएंगे। नीति निर्माता शायद जोखिम उठाएं और करों में कटौती कर वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ें या उन्हें अधिक राजकोषीय गुंजाइश मुहैया कराएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम संसाधन के लिए कर बढ़ाने की पुरानी परिपाटी पर नहीं लौटेंगे।

दूसरा अनचाहा परिणाम नोटबंदी से सामने आया। नोटबंदी के बाद हमने बैंकों और डेट म्युचुअल फंड दोनों में नकदी बढ़ती देखी। डेट फंड में पूंजी की आवक ने कॉर्पोरेट डेट बाजार को गति दी। अचानक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और आवास वित्त कंपनियां लंबी अवधि के लिए भारी पूंजी जुटाने की स्थिति में आ गईं।

फंड तक बढ़ी हुई पहुंच और सरकारी बैंकों द्वारा इन कंपनियों की वृद्धि प्रोफाइल बढ़ाने के साथ उनका मूल्यांकन कई गुना बढ़ गया। इसे बरकरार रखने के लिए उन्हें तेज वृद्धि दर्शानी पड़ी और तेज वृद्धि के लिए उन्हें इसी डेट बाजार से और अधिक राशि उठानी पड़ी। आईएलऐंडएफएस डिफॉल्ट के बाद डेट बाजार में पूंजी की आवक कम हुई और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी। इन कंपनियों में से कई इस स्तर की उधारी को संभाल नहीं सकतीं। उन्हें परिसंपत्ति और जवाबदेही के बेहतर संतुलन की आवश्यकता है। उनकी वृद्धि की महत्त्वाकांक्षा पर लगाम लगानी होगी।

डेट फंड में पूंजी का प्रवाह की बात करें तो यह फंड मोटे तौर पर समकक्ष समूह में बेचा जाता है इसलिए यह उच्च प्रतिफल देने की स्थिति में रहता है। इससे आवक बढ़ती है। कई फंड ने अपनी पूंजी उच्च जोखिम में डाली। होल्डिंग कंपनी और गैर सूचीबद्ध कंपनियों ने भी काफी अहम फंड तक पहुंच बनाई। प्रतिफल की तलाश में और अधिक जोखिम लिया गया। इन डेट फंड को ध्यान में रखें। बैंकों के उलट इनके यहां बड़े ऋण विभाग नहीं होते। वे पूरी तरह रेटिंग पर निर्भर करते हैं। जब तक उनकी रेटिंग निवेश श्रेणी की रहती है उन्हें खरीदा जा सकता है। भले ही वह प्रवर्तक की फंडिंग हो और संस्थान के पास कोई नकद प्रवाह न हो। जोखिम से बचाव के मौजूदा माहौल में यह सब बदल रहा है। डेट फंड अब और अधिक सचेत हैं। निवेशक और ज्यादा सचेत हैं।

अगर बाजार आगे बढ़ता रहता है और परिपक्व होता है तो इसे सामान्य व्यवहार माना जाएगा। हमें वृद्धि के साथ-साथ नए उपाय, नवाचारी ढांचा देखने को मिलता है और यह सब किसी भी परिसंपत्ति वर्ग के परिपक्वता चक्र में सामान्य बात है। हमारा कॉर्पोरेट डेट और ढांचागत ऋण बाजार अब परिपक्व हो रहे हैं। परिणामस्वरूप तमाम प्रतिभागी सीखेंगे और इन बाजारों को और मजबूत बनाएंगे। इस बीच जब इन बाजारों पर लगाम लगेगी तो ज्यादा जोखिम उठाने वाले कर्जदारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। परंतु यह कोई व्यवस्थागत जोखिम नहीं है। डेट बाजार अत्यावश्यक ठहराव से गुजर रहे हैं। इसके बाद वे दोबारा गति पकड़ेंगे। हम मजबूत और नवाचारी कॉर्पोरेट ऋण और ढांचागत ऋण बाजार की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि नीति निर्माता डेट बाजार की इस अपरिहार्य हलचल को लेकर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दें। हमें इन पर अतिनियमन नहीं थोपना चाहिए और नवाचार तथा जोखिम उठाने की चाह समाप्त नहीं कर देनी चाहिए।

वर्तमान में बहुत अधिक अनिश्चितता और आशंका का माहौल है लेकिन यह दौर भी समाप्त हो जाएगा। हमारे पास कहीं अधिक मजबूत और अनुशासित वित्तीय तंत्र होगा। मजबूत कंपनियां और अधिक नैतिक कारोबारी व्यवहार ही बचे रहेंगे।

निवेश जुटाने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं मांग

नीति नियम

मिहिर शर्मा

आर्थिक समीक्षा को वास्तविक बजट की तुलना में अधिक अग्रगामी और आर्थिक रूप से तर्कसंगत माना जाता है। दरअसल आर्थिक समीक्षा अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार की जाती है जबकि बजट अफसरशाहों द्वारा। हालांकि बजट को वास्तविक दुनिया से दो चार होना होता है जबकि समीक्षा तमाम अर्थशास्त्रियों की तरह आदर्श की दुनिया में भी रह सकती है। बजट और आर्थिक समीक्षा में व्यापक अंतर है। दोनों में निवेश में नई जान फूंकने को प्राथमिकता दी गई है। परंतु नीतियों के स्तर पर काफी अंतर है: समीक्षा में यह दलील सही है कि निवेश को बढ़ावा देने के किसी भी कदम में निर्यात वृद्धि अनिवार्य है।

अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाकर भी निवेश को गति दी जा सकती है। परंतु इससे एक विवाद भी उत्पन्न होता है: निजी क्षेत्र का निवेश बिना मांग के वादे के गति नहीं पकड़ेगा और बचत में इजाफा, खपत बढ़ाने की मांग का विरोधाभासी है। समीक्षा में कहा गया है, 'उच्च स्तर की बचत के कारण जीडीपी में खपत की हिस्सेदारी सीमित रहने से घरेलू खपत ज्यादा से ज्यादा उस स्थिति में ताकत बढ़ाने का काम कर सकती है जब उच्च आय वृद्धि खपत की पूर्ति करे। ऐसे में उच्च निवेश आने से जो भारी भरकम क्षमता विकसित होगी उसके लिए मांग कहां से तैयार होगी? इसका उत्तर है निर्यात। यही कारण है कि एक आक्रामक निर्यात नीति के आधार पर ही निवेश आधारित वृद्धि मॉडल बनना चाहिए।'

देश का हालिया आर्थिक इतिहास बताता है कि अगर नए निवेश के लिए केवल घरेलू खपत की मांग ही एकमात्र दलील हो तो निवेश में नई जान फूंकना मुश्किल है। कम ईंधन दरों के कारण खपत में तेजी आई लेकिन निजी क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता की समस्या हल नहीं हुई। इसने निवेश को प्रभावित किया। निर्यात 2014 से ठहरा हुआ है और हाल में वृद्धि में समस्या नजर आई। स्थायी वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। जब तक हम खपत आधारित वृद्धि की नीति तलाशेंगे ऐसा बना रहेगा।

बजट का रुख समीक्षा से अलग है। उसने निवेश के मामले में आपूर्ति क्षेत्र की दिक्कत दूर करने का प्रयास किया है लेकिन मांग क्षेत्र को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। हमारा देश निवेशकों को गति देने के लिए घरेलू मांग का संरक्षण कर रहा है, यह बड़ी चूक है। देश में निवेश कैसे आएगा? अमेरिका और चीन के बीच तनाव के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखला लड़खड़ाई हुई है। भारत की विश्व कारोबार में हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम है और वह इसका फायदा उठा सकता है। अगर विश्व व्यापार धीमी गति से बढ़ रहा है तो भी श्रम अधिशेष वाले देश की विश्व व्यापार में इतनी कम हिस्सेदारी को देखते हुए निर्यात में इजाफा किया जा सकता है। हम चीन की कुछ हिस्सेदारी पर काबिज होकर ऐसा कर सकते हैं।

अगर निवेश को बढ़ावा देना है तो हमें एक स्थिर नीतिगत माहौल के साथ-साथ ऐसी भावना की जरूरत है कि हम प्रभावी तरीके से वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बन सकता है। मौजूदा सरकार के नजरिये से मुख्य बाधा है देश का समस्याग्रस्त बुनियादी ढांचा। यह बात आंशिक रूप से सही है। समीक्षा में भी कहा गया है कि नीतिगत स्थिरता अहम है। यही बात प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होता है। बजट इन दो बाधाओं को कैसे दूर करता है?

वह इन्हें पूरी तरह हल नहीं करता। बड़ी कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार जारी है और उन्हें कॉर्पोरेट आय कर के 25 फीसदी के आधार दर दायरे से बाहर रखा गया है। ये वे कंपनियां हैं जो सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और उत्पादक हैं। ये कंपनियां ऐसे विश्वस्तरीय रोजगार तैयार करती हैं जिनकी हमें जरूरत है। इन कंपनियों पर असंगत ढंग से ऊंची कर दर इन कंपनियों को निर्यात की दृष्टि से गैर प्रतिस्पर्धी बनाती है। समीक्षा में कहा गया है, श्रम सुधार हमारी मदद कर सकते हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसा हो चुका है। परंतु हालांकि बजट में एक बार फिर श्रम कानूनों को तार्किक बनाने की बात कही गई है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लचीले श्रम कानून अभी भी दूर बने हुए हैं। नीतिगत निश्चितता की बात करें तो बजट में चीजें और खराब हुई हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में टैरिफ की स्थिरता अहम है। हम ऐसी जगह निवेश करना नहीं चाहते जहां टैरिफ से निरंतर छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती हो।

सहज, प्रतिस्पर्धी कर दर और टैरिफ की जरूरत है लेकिन इस बजट में भी आयात शुल्क में मनमाना बदलाव देखने को मिला। इससे भी बुरी बात यह है कि यह घरेलू बाजार के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत केवल अपने ग्राहकों में रुचि रखता है, उसे वैश्विक उत्पादक बनने में रुचि नहीं है। यह बात तमाम हालिया नीतियों में महसूस की जा सकती है। ये नीतियां विदेशी निवेशकों को निशाना बनाती हैं। मामला चाहे ई-कॉमर्स का हो, या भुगतान का। सरकार के आक्रामक और संरक्षणवादी रुख के कारण ही बजट भाषण में विदेशी कंपनियों का देश में बड़े विनिर्माण संयंत्र लगाने का आह्वान थोड़ा विरोधाभासी नजर आया। इसकी भाषा भी बहुत दुरूह और उलझाऊ है। पहले तो अर्थव्यवस्था को गैर प्रतिस्पर्धी बना दिया गया जिससे कोई यहां आना ही नहीं चाहता, उसके बाद इसके लिए उत्प्रेरण किया जा रहा है ताकि सत्ता राजनेताओं और नौकरशाहों के हाथ में रहे।

न केवल अल्पावधि बल्कि दीर्घावधि में भी देश के निवेश में सुधार की जरूरत है। हमें अतिशय क्षमता की समस्या को अप्रासंगिक बनाना होगा। उसके लिए हमें देश के बाहर दृष्टि डालनी होगी। ग्राहकों की संख्या देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल भ्रम है क्योंकि हर ग्राहक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे रोजगार चाहिए। एक बड़ा देश जो विकसित होने का प्रयास कर रहा है उसके सामने वैसी ही बाधाएं होती हैं जैसी छोटे देशों के सामने। मसलन उसकी अपनी मांग निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त रहती है। अर्थशास्त्री और आर्थिक समीक्षा इसे याद रखते हैं लेकिन राजनेता और बजट इसे तवज्जो नहीं देते।

कानाफूसी

कमरा नंबर 53

सन 2009 से ही संसद में बहुत कम सदस्यों के बावजूद वाम दलों, खासतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जनहित के मुद्दे लगातार उठाए हैं। संप्रग-2 के कार्यकाल के दौरान भी माकपा निरंतर संसद भवन के कमरा नंबर 53 में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करती रही। संसद सत्र के दौरान आयोजित इन सम्मेलनों में सरकार से सामाजिक और आर्थिक मसलों पर जवाब तलब किए जाते थे। अब जबकि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सांसद नहीं हैं, भाकपा के डी राजा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और इनका कोई वारिस नजर नहीं आ रहा है तो तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने इस अंतर को पाटने की कोशिश की है। उन्होंने मंगलवार को उसी कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जो समसामयिक मसलों पर केंद्रित था। वाम दल जहां सम्मेलनों के दौरान हल्का फुल्का नाश्ता कराते थे, वहीं तृणमूल की ओर से मुर्ग-मछली की दावत का इंतजाम था।

कुछ भी हो सकता है

कर्नाटक की राजनीति में आए भूचाल के बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र में 100 फीसदी उपस्थिति दर्ज कराएं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों से कहा है कि अगर किसी को अवकाश चाहिए तो उसे उचित कारण बताते हुए अग्रिम जानकारी देनी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पार्टी विधायकों से मुलाकात के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार और उसके मंत्री राज्य के मामलों को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में 'कुछ भी हो सकता है।'

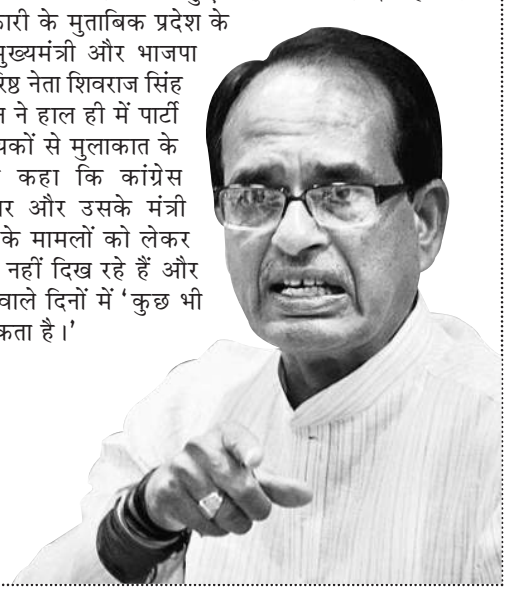

आपका पक्ष

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठे कदम

हाल में आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे में एक बस के गहरे नाले में गिरने के 29 यात्रियों की मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार तड़के चार बजे बस ड्राइवर को झपकी आ गई जिससे बस एक्सप्रेसवे का डिवाइडर तोड़ कर नाले में जा गिरी थी। इस साल अबतक एक्सप्रेसवे पर हुए विभिन्न हादसों में 77 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत वर्ष 2012 को हुई थी और तब से आज तक 5,000 से अधिक दुर्घटनाओं में लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग-अलग मौसम में दुर्घटनाओं का कारण भी अलग-अलग रहता है। ठंड के दिनों में कोहरे के कारण सड़क पर साफ दिखाई नहीं देने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। पिछले साल ठंड के दिनों में जब घना कोहरा छाया था तब दुर्घटनाओं में कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई थीं। वहीं गर्मी के दिनों में टायर फटने की घटना में वृद्धि हो जाती है। गर्मी के कारण रीसोलिंग वाले टायर की उपरी परत उखड़ने लगती है जिससे टायर फटने की घटना में वृद्धि होती है। इससे वह गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त होती ही है इसके अलावा पीछे से आ रही गाड़ियां भी उससे टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। वहीं अच्छी सड़क का होना भी दुर्घटना को आमंत्रित करती है। अच्छी सड़क होने के कारण लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और अनियंत्रित होकर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। शहरों के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना तथा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना काफी अंतर होता है। शहरों में लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती हैं तथा सड़कों पर स्पीड लिमिट लिखी होती है। अगर कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो पुलिस चालान काटती है। लेकिन एक्सप्रेसवे एक खुला मैदान जैसा होता है तथा लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अत: लोगों को एक्सप्रेसवे पर गंभीरता से गाड़ी चलानी चाहिए तथा रफ्तार तेज न हो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सरकार को एक्सप्रेसवे में जगह-जगह पर चेकप्वाइंट स्थापित करना चाहिए। जिससे तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों का चालान काटा जा सके। डिजिटलीकरण के दौर में हर 5 किलोमीटर पर कैमरे लगाए जाने चाहिए जो तय सीमा से तेज गति से चल रही गाड़ियों का तुरंत ऑनलाइन चालान कर चालक के मोबाइल में मैसेज भेज सके।

रोहित कुमार, नई दिल्ली

आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे में बस के नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी

राजस्थान में टिड्डी दल का आतंक

राजस्थान में टिड्डी दल का आतंक मचा है। राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर जिलों में टिड्डी दल ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मीडिया में आई खबर के अनुसार टिड्डी पाकिस्तान, यमन तथा ईरान से आ रहे हैं। टिड्डी दल को रोकने के लिए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। सरकार टिड्डी दल को रोकने के लिए खेतों में छिड़काव करा रही है। इसके लिए विशेष तौर पर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है तथा वाहनों का इंतजाम किया गया है। ये टिड्डी विदेशों से आ रहे हैं जो राज्य में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डी खेतों में खड़ी फसलों को पूरा चट कर जाते हैं तथा लोगों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इससे बचने के लिए रासायनिक छिड़काव किया जाता है जिससे वे फसल को बरबाद न कर सकें। किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है।

अरुण कुमार, जोधपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।